Koraput railway line is one of them. The construction of this rail link within the time-bound programme is very necessary as the entire materials required for the construction of the world's biggest aluminium plant at Damanjodi in Koraput district of Orissa are proposed to be trannsported through this railway route. Another important project, Rs. 20 crore Mancheswar railway workshop, located at Orissa, is under construction. The offices of the Senior Engineers and other administrative offices for the Cuttack-Paradeep line and the Mancheswar railway workshop are located at Calcutta. The location of important offices outside the State causes great discontentment amongst local people, as the people connected with the construction activities have to travel to Calcutta for pursuing various matters. In the process, the construction work of the on-going projects are being delayed and cannot be completed before the target period.

The meaning of a Construction Office in Orissa will enable the details to expedite the completion of the project work. It will provide a great relief to the people connected with the various construction activities. Therefore, the opening of a Construction Office in Orissa deserves the special attention of the Government of India.

In view of this, I demand that a Construction Office of the Ministry of Railway should be opened in Orissa forthwith.

(ii) Delay in repair of the steps of Qutab Minar.

श्री तारिक अनवर (कटिहार): उपाध्यक्ष महोदय, काफी दिनों पूर्व कुतुब दुर्घटना की जांच करने वाले एक सदस्यीय जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि कुतुब की सीढ़ियों की मरम्मत कराई जाए तथा इसके अतिरिक्त भी कई अन्य सुझाव आयोग ने दिये थे। उक्त दुर्घटना में 45 व्यक्तियों की जानें गईं थीं ।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन द्वारा सीढ़ियों की मरम्मत के लिए सम्भवत: 22 हजार रूपए स्वीकृत किए गए । यह भी जानकारी मिली है कि सरकार ने मरम्मत के लिए प्राथमिकता के आधार पर सीमेंट उपलब्ध कराया है किन्तु आज तक मरम्मत का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है । ऐसा समाचार है कि जो सीमेन्ट इस उद्देश्य के लिए है उसके वितरण में अनियमितायें हैं । अनाधिकृत व्यक्ति वहां पर गाइड हैं और किताब बेच रहे हैं ।

इस प्रकार का अनैतिक कार्य करने वालों को दंडित तो किया ही जाना चाहिए, साथ ही इसके सही और पूरे तथ्य सामने आ सकें, इसके लिए यह आवश्यक है कि केन्द्रीय गुप्तचर विभाग द्वारा सारे मामले की जांच कराई जाए । मैं मंत्री महोदय से यह भी अनुरोध करूंगा कि वे सदन को बतायें कि मरम्मत आदि के कार्य में विलम्ब के क्या कारण रहे और उसके लिए कौन अधिकारी दोषी है ।

(iii) Steps to arrange more power for Rajasthan from adjoining States.

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रान्त को इस समय देश के सबसे बड़े विद्युत संकट का सामना करना पड़ रहा है । सन् 1980 में कृषि क्षेत्र में किसानों को दिन में 6 घंटे बिजली, सन् 1981 में घंटे बिजली और सन् 1982 में 4 घंटे बिजली मिलती थी और उस समय भी वह आंख मिचौली करती थी । सन् 1980 में बड़े उद्योगों में 33 प्रतिशत कटौती, सन् 1981 में 44 प्रतिशत कटौती और सन् 1982 से 50 प्रतिशत से भी अधिक कटौती की गई । वर्षा के दिनों में तीन से चार महीने तक लगातार 100-100 प्रतिशत कटौती की गई । लघु उद्योगों में भी 30 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक कटौती रही ।

औद्योगिक उत्पादन में राज्य में सन् 1980 में 3500 करोड़ रूपये, सन् 81 में 45,00 करोड़ रूपये एवं सन् 82 में 6,000करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और कृषि क्षेत्र में रबी की फसल में 25 से 30 प्रतिशत कम पैदावार हुई और किसानों को करोड़ों रुपये की हानी हुई जिसके